ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN NO.: 2347-2944, RNI : UPBIL04292,REG. No.: 561/2013-2014Vol.-2,No.-2 **PP-419-422**,YEAR-2014

भारत के कृषि क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव

☐ डॉ0 अजीत कुमार सिंह

सारांश *– वैश्वीकरण एक सतत एवं अनवरत प्रक्रिया है, जो प्रमुख रूप से दो अवधारणाओं–आधुनिकीकरण एवं उदारीकरण पर आधारित है। वास्तव में, आधुनिकीकरण के बहुत पूर्व ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। वैश्वीकरण मूल रूप से एक आर्थिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समाजों, संस्कृतियों, संचार परिवहन और व्यापार को वैश्विक अन्तर्सम्बन्ध के माध्यम से एकीकृत करने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा व्यापार, विदेशी पूँजी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, पूँजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध् यम से अर्न्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण का प्रयास किया जाता है। भारत में वर्ष 1990 के पूर्व इस दिशा में न तो किसी ने विचार किया और न ही कोई प्रयास हुआ, किन्तु इसके बाद कुछ वांछित क्षेत्रों में प्रभावी परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किया गया। सरकार इस बात से प्रसन्न थी कि आर्थिक प्रगति की दर 8 से 10 प्रतिशत सम्भावित है, तो आलोचक इस बात से चिन्तित थे कि धनी और अधिक धनी तथा गरीब और अधिक गरीब हो जाएँगे या नगरीय क्षेत्रों का विकास और अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्र और अधिक पिछड़ जाएँगें। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री जी ने 1998 के एक उद्‌बोधन में कहा था कि वैश्वीकरण की, जो सूचना के स्वतंत्र प्रवाह और तकनीकी की तेज प्रगति पर बल देगा। कोई भी देश अनदेखी नहीं कर सकता, किन्तु यह भी सत्य है कि इसके लिए बाजार का अनुशासित होना अत्यन्त आवश्यक है।*

आधुनिकीकरण एवं उदारीकरण भी एक दूसरे से अन्तर्संबंधित और अन्योन्याश्रित है। आधुनिकीकरण वैज्ञानिक व तार्किक रीति से प्रेरित वैचारिकी एवं अनुपालन को व्यक्त करता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो जीवन के सभी अंगों व कारकों को प्रभावित करता है। जब कि उदारीकरण आर्थिक प्रक्रिया को व्यक्त करता है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण दोनो ही आर्थिक सुधार की योजनाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम व दिशा देने का प्रयास करते है। कहा जाता है कि इससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की विकास योजनाओं को गति प्रदान किया जा सकता है। उदारीकरण आर्थिक क्रिया कलापों पर राज्य के नियंत्रण को कम करके किया जा सकता है, क्योंकि राज्य के पूर्ण नियंत्रण से निश्चलता या प्रगतिरुद्धता आती है व अक्षमता में वृद्धि होती है और इसे दूर करने के लिए निजीकरण आवश्यक है। इससे प्रतियोगिता को प्रोत्साहित कर विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है।

उदारीकरण भी दो प्रकार का होता है आन्तरिक व बाह्य। आन्तरिक उदारीकरण के अन्तर्गत व्यापार में सहभागियों को अपनी आवश्यकताओं – उत्पादन उपयोग कीमत, बाजार, ऋण निवेश, आदि में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है, जबकि वाह्यउदारीकरण का संबंध विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश की छूट, आयात शुल्क में

कटौती आदि से होता है इसका प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक से अधिक सहभागिता करना तथा देश के अन्दर बाहरी देशों को पूँजी निवेश के लिए प्रेरित करना होता है जिससे विकास की दर में वृद्धि को कम से कम समय में प्राप्त किया जा सके। अतः बिना उदारीकरण के वैश्वीकरण संभव नहीं हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण एक जान बूझकर अपनायी गयी आर्थिक नीति है। यह अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण की अनवरत प्रक्रिया है जिससे निधि व्यापार, तकनीकी, सूचना व ज्ञान के प्रवाह को अबाध गति से प्रवाहित

सहायक प्रोफेसर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, श्री मु० म० टा० पी०जी० कॉलेज, बलिया (उ०प्र०) भारत।

करने में मद्द मिलेगी, जिससे रोग, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में आशातीत लाभ मिलने की आशा की जा सकती है। पिछले वर्षों में वैश्वीकरण के प्रयास से विश्व व्यापार में बारह गुना वृद्धि और सकल घरेलू

उत्पाद में डेढ़ गुना वृद्धि हुई। विश्व व्यापार में वृद्धि के साथ–साथ गतिशीलता में विदेशी विनिमय आदि में भी बड़ी तेजी से परिवर्तन होता है। मानवीय विषमताओं को कम करने में सहायता मिलेगी। अन्य लाभ के अन्तर्गत आय की असमानता भयंकर निर्धनता, भ्रष्टाचार, नौकरशाही के विकास, उत्पादकता में कमी

आर्थिक स्रोतों के व्यापक दुरूपयोग को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसकी गंभीरता का आभास होने पर चीन जैसे देश ने भी 1979 में और भारत ने 1991में इसे सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह भी सत्य है कि इतने बड़े–बड़े देश भी दुनिया के अन्य देशों से अलग–थलग नहीं रह सकते है, इसलिए लंका, थाईलैंड, तुर्की, मलेशिया जैसे कम आय वाले देशों ने भी इसे अपना लिया। इसमें सकारात्मक के साथ–साथ नकारात्मक प्रभाव भी सम्भावित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय

एकीकरण की इस प्रक्रिया में सम्मिलित देशों के समक्ष व्यापार में उतार– चढ़ाव, उत्पादन व निवेश की अनिश्चितता का खतरा सदैव बना रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी में मंदी इसका ताजा उदाहरण है। इससे कल्याणकारी क्रिया कलापों को आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अंतरिक्ष अभियान अपव्यय विदेशी विनिमय को प्रभावित कर सकता है। विश्व की आय का 82 प्रतिशत भाग 20 प्रतिशत लोगों के पास सुरक्षित हैं जबकि नीचे के 20 प्रतिशत निर्धन लोगों के पास कुल आय का केवल 1.4 प्रतिशत ही है। आय के इस असमान वितरण के कारण धनी और अधिक धनी तथा निर्धन और अधिक निर्धन होते जा रहे है। सैद्धान्तिक रूप से आधुनिकीकरण और व्यवहारिक रूप से पश्चिमीकरण के अन्धाधुन्ध अनुकरण से जीवन शैली अत्यन्तं खर्चीली होती जा रही है। उत्पादन व आवागमन के साधनों में तेल का खर्च बढ़ेगा जिससे व्यापार व निवेश प्रभावित होगा। तथा पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा। सार्वभौम प्रतिमानो के विकास का अर्थ क्षेत्रीय संस्कृतियाँ का लोप होगा। प्रत्येक स्थान पर एक जैसा यातायात, सामान, शिल्पकारी, आदि दिखेगा। और क्षेत्रीय कला, शिल्पकारी, या अन्य विशिष्टताएँ लुप्त हो जाएँगी। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि स्वतंत्र व्यापार एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता की नीति इस बात का आश्वासन नहीं दे सकती है कि वे आवश्यकता भर ही जल, वायु, वन, ऊर्जा और पर्यावरण के स्रोतों विशेष रूप से प्रकृति प्रदत्त स्रोतों का दोहन करेगी। लाभ अर्जित करने की प्रवृत्ति इस बात का ध्यान नहीं रखने देगी। वैश्वीकरण के पूँजीवादी प्रवृत्ति से अनेक ज्वलंत प्रश्न उभरते हैं।

1. क्या अनियंत्रिता विदेशी पूँजी के निवेश व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश देश के लिए हितकर होगा।
2. देश के आर्थिक क्रियाओं में राज्य की भूमिका का कमजोर होना हितकर होगा।
3. पूर्वी एशिया के 1997–98 की स्थिति दोहराई जाऐगी।
4. श्रम शक्ति की अधिकता वाले देशों में निजीकरण की स्थिति क्या होगी।
5. क्या वैश्वीकरण से पर्यावारण नष्ट हो जाएगा।
6. सृजनात्मक विकास की क्या स्थिति होगी।
7. औद्योगिक केन्द्रीकरण के मापन का आधार क्या होगा। और इसका क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
8. सार्वजनिक उपयोग एवं औद्योगिक जाल में प्रतियोगिता प्रोत्साहन की प्रक्रिया क्या होगी।
9. विश्व व्यापार में सुरक्षा के क्या उपाय होंगे।
10. दवाओं के मूल्य क्या आम आदमी की पहुँच बाहर हो जाएगा।

भारत एक कृषिप्रधान देश है इसकी 80 प्रतिशत जनता गाँवो में रहती है तथा इसकी 60

प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर आश्रित है किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का इस क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अतः इसका मूल्यांकन अपरिहार्य है। भारत को आणविक शक्ति से पूर्व कृषि शक्ति के रूप में स्थापित करना होगा– (डॉ. एम०एस० स्वामीनाथन)। प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सिचाई की ओर ध्यान देने के बाद भी 1966–67 में देशवासियों को अनाजों की अपर्याप्तता का संकट झेलना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री के दृढ़ प्रतिज्ञ प्रयास से देश इस संकट से उबर सका था। बांगलादेश जैसे देश के दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र में वैश्वीकरण के प्रभाव में बहुत से छोटे बड़े किसानों ने चावल की खेती छोड़कर मछली का व्यापार स्वीकार कर लिया। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बनाये रखने में परिस्थितिकीय और व्यवस्थापकीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पूरी व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की अपेक्षाओं के लिए पूँजी की आवश्यकता पड़ रही थी जो उनके पास नहीं था। भारत में कृषि क्षेत्र के समक्ष जो प्रमुख समस्याएँ अनुभव की गईं उनमें सिंचाई के लिए जल स्रोतों की कमी, उन्नत बीज की अनुपलब्धता, ऋण व बीमा सुविधाओं की अपर्याप्तता, जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता, बाजार की कमी, बिचौलियों का प्रभुत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य व आवागमन के साधनों की कमी प्रमुख है। भारत में प्रथम हरित क्रांति के साथ व्यापक जल स्रोतों के उपयोग व दुरूपयोग से जल स्रोतों की भारी कमी महसूस की गई। इससे प्रदूषण संबंधी समस्याएँ भी उत्पन्न होने लगीं। उदारीकरण के पश्चात् निजीकरण के प्रोत्साहन के साथ साथ बिचौलियों का बाजार पर नियंत्रण बढ़ता गया और किसान अपनी उपज के वास्तविक लाभ से वंचित होता चला गया। यहाँ तक की किसानों को आत्महत्या करनी पड़ गई। वर्ष 2004 तक एक लाख किसानों ने आत्महत्या की (माननीय श्री शरद पवार, कृषि मंत्री) और केवल 2006 में यह संख्या 17060 थी, (NCRB) किन्तु फिर भी समस्या को दूर करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किया जा सका। कृषि क्षेत्र में बाजारीकरण और निजीकरण के कारण उन्नत किस्म के बीजों को आम किसानों तक नहीं पंहुँचाया जा सका सी– मैप जैसी संस्था द्वारा प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम भी कुछ लोगों तक सीमित रह गया।प्रचार–प्रसार का अभाव व आम किसानों में उत्साह की कमी थी। राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण बैंक NABAD के फैलाव के बावजूद आम किसान इसके लाभ से अभी भी वंचित है। प्राकृतिक आपदाओं बाद सूखा, जलवायु की परिवर्तनशीलता मृदा परीक्षण की सुविधाओं की कमी भी कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाल रही है।कृषि क्षेत्र में न तो सरकारी स्तर पर और न ही निजी स्तर पर पूँजी का पर्याप्त निवेश हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र का विकास बहुत ही धीमी गति से हो रहा है तथा यह वैयक्तिक व राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने में पूर्णतया असमर्थ है और इस क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने एवं इसमें सृजन शक्ति विकसित करने में बहुत कठिनाई हो रही हैं। डॉ. मैथ्यू अर्थयाल भी कहते हैं कि हम भारत के सर्वोत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी, की चर्चा सुनते हैं किन्तु कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बातें सुनने को नहीं मिलतीं। पूरे एशिया में खरबपतियों की संख्या सबसे अधिक भारत में है।पूरी दुनिया के एक तिहाई पशुधन भारत में है, किन्तु यह भी सत्य है कि पूरी दुनिया के आधे सबसे अधिक गरीब भी भारत के ही हैं। लोगों के प्रबल विरोध के बावजूद विशेष आर्थिक जोन की नीति लागू कर दी गई। 2005 में इस नीति के अन्तर्गत 400 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया जिसमें पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम भी था। खासानोकी महोदय के अनुसार 1991 से 2003 के बीच पाँच मिलियन हेक्टेयर भूमि कृषि छोड़कर अन्य कार्यों के लिए अधिगृहीत किया गया, जो पिछले 40 वर्षों के दौरान अधिगृहित भूमि का आधा है इससे ज्ञात होता है कि वैश्वीकरण से औद्योगीकरण को बल मिलेगा, किन्तु कृषि क्षेत्र को भारी क्षति का

सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार मुम्बई में कुल भूमि का एक तिहाई 10,120, हेक्टेयर रिलायन्स कम्पनी के लिए अधिगृहित हुई, किन्तु जन विरोध के कारण 5000 हेक्टेयर ही दी गई 1991 में वैश्वीकरण के अन्तर्गत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू किया गया जिसके आधार पर तथा विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश, विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया गया। आयात–निर्यात नीति को उदारीकृत किया गया, अनेक उत्पादों का आयात शुल्क घटाया गया, कृषि क्षेत्र में निवेश कम किया गया तथा औद्योगीकरण में निजीकरण को प्रोत्साहित किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन दो समूहों ठच्स् एवं ।च्स् का गठन किया गया, किन्तु भ्रष्टाचार तथा गोदामों में सड़ रहे अनाजों को राशन दुकान के लिए भेजने के कारण गरीबों तक यह लाभ नहीं पहुँच सका। 1990 में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि की दर 4 प्रतिशत थी जो जनसंख्या में वृद्धि की दर से बहुत कम था, तब भी खाद्यान्न के विषय में आत्म निर्भर होने के साथ–साथ गेहूँ व चावल का निर्यात भी करने लगे लेकिन उदारीकरण के पश्चात् यह वृद्धि दर 2 प्रतिशत हो गई। दशवीं पंचवर्षीय योजना के काल में यह घटकर एक प्रतिशत हो गया। अतः भारत को उँचें दाम पर खाद्यान्न आयात करना पड़ गया। यह उदारीकरण या वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्ष को व्यक्त करता है। कृषि लाभदायक न होने के कारण बेरोजगारी भी निरन्तर बढ़ने लगी है। रोजगार की स्थिति वर्ष 1983–84 में 2.07 प्रतिशत थी जो 1993–2000 में 0.66 प्रतिशत हो गयी, किसानों, दलितों और आदिवासियों के समक्ष भयंकर बेरोजगारी की स्थिति आ गई। उर्वरकों पर नियंत्रण तथा दाम में छूट को घटाने के कारण भी कृषि क्षेत्र को अधिक क्षति हुई। बैंकों के लाभ कमाने की प्रवृति से कृषि क्षेत्र में ऋण की व्यवस्था को काफी धक्का लगा। उदारीकरण के बाद कृषि क्षेत्र में सरकार का निवेश भी कम हुआ। 1986–90 में यह कुल आय का 14.5 प्रतिशत या जो 1995–2000 में 6 प्रतिशत हो गया। उपर्याकित अवरोधो, में जीवन यापन कर रहे किसानों को निरन्तर जीविकोंपार्जन के साधन छिन जाने का भय सताने लगा। पहले जमीदारों, भूपतियों की उपेक्षाओं व शोषण की नीति झेल रहे किसान अब सरकार की उपेक्षाओं से त्रस्त प्रतीत होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास सूचकांक भी प्रभावित होकर नकारात्मकदिशा की ओर मुड़ गया आज भी सारे गाँवों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, आवागमन, आर्थिक सहयोग की निश्चितता नहीं है अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन असंभव दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण का कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक ही प्रभाव होगा, जो देश के लिए हितकर नहीं होगा। इससे बचने के लिए बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जो राजनीतिक दलो में अदूरदर्शिता के कारण संभव नहीं दिखाई देता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Contemporary Issues in Globalization - An Introduction to Theory and Policy in India. Soumyen Sikdar Oxford Uni-versity Press-2010.
2. Globalization and Agrarian change: a case of freshwater prawn farming in Bangladesh. Furo-cho, Chikusa-ku School of International Development at Nagoya University, Nagoya, Japan.
3. Globalization and Agrarian Crisis: Gaps and Gonnects Jagadish Nath, Faculty Member, Icfai National College, Guwahti.
4. Globalization and Agrarian Crisis: Farmers Suicides in In-dia- By: Prof. Ramulu Neela Professor of Sociology at Kakatiya University, Warangal, Andhra Pradesh.
5. Agrarian Crisis in India is a Creation of the Policy of Glo-balization. Dr. Mathew Aerthayil, Director of the Indian Social Institute, Bangalore.